

## दिल्ली उच्च न्यायालय का 'जीरो पेंडेंसी प्रोजेक्ट'

### चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रायोगिक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें कहा गया कि न्यायालय में लंबित सभी मुकदमों को एक वर्ष में नपिटाने हेतु वर्तमान न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है।

### अल्प विश्वसनीय संस्था (Less Credible System)

- जीरो पेंडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट (Zero Pendency Courts Project) अपनी तरह की एकलौती ऐसी योजना है जिससे विभिन्न प्रकार के मामलों हेतु समयसीमा तथा न्यायाधीशों की संख्या नश्चिन्ता करने में सहायता मिलेगी।
- रिपोर्ट के अनुसार, न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया में लगातार देरी होने से पक्षकारों को नरिणय मलिनने में दशकों लग जाते हैं जिससे न्यायालय के प्रति विश्वास में कमी आने लगती है।
- प्रतर्विर्ष मुकदमों की बढ़ती संख्या के कारण न्यायपालिका पर लंबित मुकदमों का बोझ तीव्र दर से बढ़ रहा है। अतः इस समस्या से उभरने के लिये शीघ्र ही कोई व्यवस्थित योजना बनानी होगी।
- वर्ष 2016 में यह अनुमान लगाया गया कि भारत में न्यायिक देरी और इससे संबंधित रख-रखाव में सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) का 1.5% खर्च होता है।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया और नयित समय पर नरिणय देने से संबंधित अध्ययन के लिये अपने कुछ अधीनस्थ न्यायालयों में जनवरी 2017 में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की।

- प्रोजेक्ट का प्राथमिक लक्ष्य लंबित मुकदमों को नसितारति करने के पश्चात् मुकदमों के दायर होने की दर ज्ञात करना है।
- रपौर्ट में बताया गया कदिल्ली में आपराधकि मुकदमों की संख्या, सविलि मुकदमों से बहुत अधकि है।
- 20 मार्च, 2019 तक 5.5 लाख आपराधकि मुकदमे और 1.8 लाख सविलि मुकदमे दलिली के अधीनस्थ न्यायालयों में लंबति हैं।
- यह भी उल्लेखनीय है ककिसी मुकदमें का नरिणय करने में सबसे अधकि समय लगता है और काफी समय मुकदमों को सुनने और लखिने एवं उससे संबंधति नयिर्मों को खोजने आदि में खराब होता है। इसलयि नरिणय देने में काफी देरी होती है।

## वलंब का कारण

- इस रपौर्ट के मुताबकि, सबूतों का अभाव भी मामलों में देरी के मूल कारणों में से एक है।
- चूँकिसाक्षय कसिी भी मुकदमें का आधार होते हैं, अतः इनको एकतरति करने में जतिनी देरी होती है उसका सीधा प्रभाव वाद की न्यायकि प्रक्रयिा पर पड़ता है। इसके साथ ही बाहरी पक्षकारों को सम्मन जारी करने में देरी होती है।
- इसके अतरिकित अधविक्ताओं और पक्षकारों द्वारा मुकदमें के हर स्तर पर अनावश्यक रूप से कार्यवाही को प्रभावति कयिा जाता है।
- दूरस्थ क्षेत्रों के नविासी पक्षकारों को सम्मन जारी करने में भी देरी होती है इसलयि न्यायकि प्रक्रयिा में अधकि वलंब होता है।
- इस रपौर्ट में कहा गया है कन्यायाधीशों की कमी के कारण कार्य का बोझ बढ़ जाता है।
- अतः लंबति मुकदमों के नश्चिति समय में नसितारण हेतु न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जरूरत है और वर्तमान न्यायाधीशों की संख्या 143 से 186 करने की आवश्यकता है।

और पढ़ें...

[डेटा पॉइंट: न्याय में देरी का गणति](#)

स्रोत- द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/capital-needs-43-more-judges-to-clear-pending-cases-in-1-year>

